ISSN: 2582-5526 www.thevoiceofcreativeresearch.com

The Voice of Creative Research

Vol. 8 & Issue 3 (July 2026)

Peer Reviewed Article

DOI: https://doi.org/10.53032/tvcr/2026.v8n3.23

समावेशी शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका का अध्ययन: भारतीय संदर्भ में

सिम्मी सोनकर,
(शोधार्थी)
शिक्षा शास्त्र विभाग
लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई-मेल: simmianandsv@gmail.com
https://orcid.org/0009-0002-2140-2642

डॉ० विभा यादव,
(सहायक आचार्य)
शिक्षा शास्त्र विभाग
महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ
ई-मेल: vibhayadavnew265@gmail.com

सारांश

प्रस्तुत अध्ययन भारतीय संदर्भ में समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन तथा दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्यधारा की शिक्षा से जोड़ने में विद्यालयी नेतृत्व की भूमिका का विश्लेषण करता है। समावेशी शिक्षा केवल दिव्यांग विद्यार्थियों को सामान्य विद्यालयों में प्रवेश प्रदान करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके लिए समान अवसर, सम्मानजनक वातावरण, आवश्यक शैक्षिक संसाधन, सुगम्य अधिगम व्यवस्था तथा सामाजिक सहभागिता सुनिश्चित करना भी इसका महत्वपूर्ण पक्ष है। इस संदर्भ में विद्यालय प्रधानाचार्य, शिक्षक, प्रशासन तथा राज्य और जिला स्तर के शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अध्ययन का उद्देश्य समावेशी विद्यालय नेतृत्व के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए अधिक प्रभावी और उत्तरदायी नेतृत्व व्यवस्था विकसित करने हेतु सुझाव प्रस्तुत करना है। शोध में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, संबंधित सरकारी नीतियों एवं प्रतिवेदनों तथा उपलब्ध शोध-पत्रों का दस्तावेजीय एवं साहित्यिक विश्लेषण किया गया है। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि नीतिगत प्रावधानों के बावजूद बुनियादी ढांचे की कमी, सुगम्य सुविधाओं का अभाव, प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी, संसाधनों की अपर्याप्तता, प्रशासनिक उदासीनता तथा राज्य एवं जिला स्तर पर प्रभावी नेतृत्व और निगरानी की कमी समावेशी शिक्षा के मार्ग में प्रमुख बाधाएँ हैं। कुछ विद्यालयों में विद्यार्थियों द्वारा विरोध प्रदर्शन की घटनाएँ भी इन संरचनात्मक समस्याओं की ओर संकेत करती हैं। अतः समावेशी शिक्षा के सफल क्रियान्वयन के लिए संवेदनशील, सहभागी, उत्तरदायी और साक्ष्य-आधारित विद्यालय नेतृत्व को मजबूत करना आवश्यक है।

मुख्य शब्द: समावेशी शिक्षा, विद्यालय नेतृत्व, दिव्यांग विद्यार्थी, शैक्षिक समानता, नेतृत्व चुनौतियाँ, विद्यालयी वातावरण

परिचय

दशकों से, शिक्षा प्रणाली ने दिव्यांग बच्चों को मुख्यधारा के विद्यालयों में एकीकृत करने के विचार को या तो नजरअंदाज किया है या इसके साथ संघर्ष किया है। इसलिए समावेशन केवल कागजों पर एक लक्ष्य बनकर रह गया है। समावेशी शिक्षा के लिए नया अधिकार-आधारित दृष्टिकोण इसलिए एक न्यायसंगत और समान समाज के निर्माण की दिशा में एक सही कदम है।

दिव्यांगजनों को मुख्य धारा से जोड़ने, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने, उनमें आत्मविश्वास जगाने हेतु समावेशी शिक्षा एक प्रमुख साधन है, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है, इसके सफल क्रियान्वयन एवं निगरानी हेतु विशेषज्ञों द्वारा समावेशी विद्यालय नेतृत्व की ओर ध्यान आकर्षित करने और लागू करने की पहल की जा रही है। यह समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का अध्ययन करने मजबूत संगठनात्मक ढांचे का निर्माण, विद्यालय को दिशा निर्देश, वर्तमान में उत्पन्न समस्याओं के समाधान, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, निगरानी और देखरेख हेतु महत्वपूर्ण है। इन सभी कार्य हेतु समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति(2020) के अनुसार, भारत द्वारा 2015 में अपने गए सतत विकास के वैश्विक एजेंडा के लक्ष्य- 4 को 2030 तक सभी के लिए समावेशी और सामान गुणवत्ता वाली शिक्षा सुनिश्चित करना और आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना। परंतु वर्तमान समय की समस्याओं को देखते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन कार्य है, अभी हाल ही में जयपुर के सेठ आनंदीलाल पोद्दार मूक-बधिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में खराब बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी के कारण विद्यार्थियों ने मौन विरोध प्रदर्शन किया, इस तरह की समस्याओं के लिए ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है जो स्कूलों की खराब स्थिति, प्रशासन का कठोर रवैया, संसाधनों की कमी जैसी समस्याओं के समाधान हेतु तत्कालीन निदान करें। दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर परिवारों से अधिक वसूली की जाती है यहां शिक्षा का व्यवसायीकरण विस्तृत रूप लेता जा रहा है। वर्तमान में, विकलांग व्यक्तियों की शैक्षिक, सामाजिक, शारीरिक, आर्थिक और अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत में समय-समय पर नीतियां बनाई जाती हैं और कानून बनाए जाते हैं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगजनों को समान अधिकार और सम्मान मिले। इन नीतियों के सफल कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की है। ये संगठन अपनी क्षमता भर अपना योगदान देते हैं, लेकिन वास्तव में राज्य और जिला स्तर पर इन नीतियों और कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नेतृत्व की कमी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 में कहा गया है कि भारतीय शिक्षा प्रणाली और लगातार सरकारी नीतियों ने स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर लैंगिक और सामाजिक श्रेणियों में अंतर को कम करने में लगातार प्रगति की है। हालांकि, असमानताएं अभी भी दिखाई दे रही है।

संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संगठन (यूनेस्को) के अनुसार, भारत में समावेशी शिक्षा यानी सभी के लिए समान अवसरों वाली शिक्षा प्रणाली को लागू करना जटिल कार्य है और विभिन्न संदर्भ में बच्चों और उनके परिवारों की विविध आवश्यकताओं की एक अच्छी समझ विकसित करने की आवश्यकता है।

यूनेस्को की रिपोर्ट,2019 'स्टेट आफ द एजुकेशन रिपोर्ट फॉर इंडिया चिल्ड्रन्स विद डिसेबिलिटी' में भारतीय विकलांग बच्चों को शिक्षा में समावेशी भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु 10 प्रमुख सिफारिशें दी गई है, जिनमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा की विशिष्ट समस्याओं को शामिल करते हुए आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम के साथ सामंजस्य हेतु शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन करने, शिक्षा कार्यक्रमों के प्रभावी संकेंद्रण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत एक समन्वय तंत्र स्थापित करने, सीखने की जरूरत को पूरा करने के लिए शिक्षा बजट में विशिष्ट और पर्याप्त वित्तीय आवंटन सुनिश्चित करने, नियोजन कार्यान्वयन और निगरानी हेतु डाटा प्रणालियों का सशक्तिकरण करने, स्कूल पारिस्थितिकी प्रणालियों को समृद्ध बनाने और निगरानी हेतु डाटा प्रणालियों का सशक्तिकरण करने, शिक्षा के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का विस्तार करने, सभी को अवसर प्रदान करने, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करने, रूढ़िवादी विचारों में बदलाव करने तथा निजी क्षेत्र और स्थानीय समुदायों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु सुझाव दिए गए हैं।(यूनेस्को,2019)

नेतृत्व

नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो लोगों को इस तरह से प्रभावित करती है कि वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति करने का प्रयास करें। एक अच्छे नेता का गुण है कि वह शिक्षित हो,और जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हो आलोचना और परिवर्तन के लिए सदैव तैयार हो। नेतृत्व को दिशा प्रदान करने और प्रभाव लागू करने की प्रक्रिया के रूप में समझा जाता है (लुम्बी और कोलमैन, 2016)। इसमें दूसरों को पसंदीदा दिशा की ओर प्रभावित करने के लिए लोगों

की भावनाओं, विचारों और कार्यों को निर्णायक रूप से प्रबंधित करना शामिल है (डायमंड एंड स्पिलेन, 2016)। स्कूल नेतृत्व समावेशी शिक्षा के सफल कार्यान्वयन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। "स्कूल नेतृत्व का समावेशी स्कूल अभ्यास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थियों के लिए सकारात्मक परिणामों से जुड़ा हुआ है" (मैक रुएर्क, 2013)। स्कूल के नेताओं को किसी भी परिवर्तन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माना जाता है जिसका उद्देश्य समावेशी स्कूलों में सभी शिक्षार्थियों की उपलब्धि और कल्याण को बढ़ाना है" (डोनेली, ओ मर्चू एंड थिस, 2016)।

समावेशी विद्यालय नेतृत्व की भूमिका

स्कूल नेतृत्व समावेशी शिक्षा की सफल क्रियान्वयन में एक केंद्रीय भूमिका निभाता है इनका समावेशी स्कूल अभ्यास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है क्योंकि यह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षार्थियों के लिए सकारात्मक परिणाम से जुड़ा हुआ होता है।

समावेशी शिक्षा

समावेशी शिक्षा वह है जिसमें विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों और सामान्य विद्यार्थियों को एक ही कक्षा में एक साथ सीखने का अवसर प्रदान किया जाता है। इसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार यह शिक्षा का एक व्यावहारिक समाधान है जो शिक्षार्थियों के अलगाव का विरोध करती है।

समावेशी शिक्षा की आवश्यकता

समावेशी शिक्षा विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थी को सामान्य विद्यार्थियों के साथ सीखने का अवसर प्रदान करने, क्षमताओं को विकसित करने, सामाजिक एकीकरण को सुनिश्चित करने, सकारात्मक एवं व्यवहारिक वातावरण उत्पन्न करने हेतु आवश्यक है। यह दृष्टिकोण विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को अपने साथियों के साथ समान रूप से सीखने और प्रगति करने का अवसर प्रदान करता है। यह कम खर्चीली होने के साथ-साथ विभिन्नताओं को दूर करने में अधिक प्रभावी है।

समावेशी शिक्षा में चुनौतियाँ

समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चुनौतियां उत्पन्न होती हैं जिनके कारण सफल परिणाम देखने को नहीं मिलते यह इस प्रकार है-

- समावेशी स्कूलों का अभाव - वर्तमान समय में कुछ ही विद्यालय हैं जहां समावेशी शिक्षा प्रदान की जाती है ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास विशेष शिक्षक नहीं है जिसकी वजह से वहां विशेष विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण नहीं कराई जाती है।
- आवासीय विद्यालय योजना का सफल न हो पाना - आवासीय विद्यालय योजना दूर दराज के क्षेत्र में रहने वाले विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिए बनाई गई थी, परंतु वर्तमान समय में दो या चार विद्यालय ही एक जनपदों में देखने को मिलते हैं, और कहीं-कहीं तो अभी विद्यालयों का निर्माण ही नहीं किया गया है।
- भौतिक संसाधनों की कमी - अधिकांश विद्यालयों में अभी भी रैंप, विशेष शौचालय, संसाधन कक्षा और सहायक उपकरणों जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, इस वजह से विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
- प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी - समावेशी कक्षा में पढ़ने के लिए विशेष शिक्षकों की भारी कमी है, जिस कारण अधिकांश शिक्षक विशेष विद्यार्थियों की भावनात्मक और शैक्षिक आवश्यकताओं को समझने में असमर्थ रहते हैं।

दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा एवं कल्याण हेतु प्रभावी नीतियां

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 – एन. ई. पी. 1986 के अनुसार, मूल सिद्धांत यह है कि प्रत्येक शिक्षार्थी को जाति, पंथ, स्थान या लिंग के आधार पर किसी भी भेदभाव के बिना एक निश्चित स्तर तक अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य, उन्हें समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में सक्षम बनाना है।
- भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम,1992 - इसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मानसिक और सामाजिक स्तरों पर सक्षम बनाना है

- राष्ट्रीय न्यास अधिनियम, 1999 - इस ट्रस्ट की स्थापना 30 दिसंबर 1999 को ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और बहु-विकलांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण और उससे जुड़े मामलों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के निकाय के रूप में की गई थी।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय नीति, 2006 - इसका उद्देश्य समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और समाज में विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके लिए, निम्नलिखित क्षेत्रों को संबोधित किया गया है: विकलांगता की रोकथाम, विकलांगता का शीघ्र पता लगाने सहित पुनर्वास उपाय, परिवार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी, सहायक उपकरणों का प्रावधान, विकलांग व्यक्तियों के लिए शिक्षा का प्रावधान, आर्थिक पुनर्वास, सरकारी प्रतिष्ठानों में रोजगार, निजी क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार, विकलांग महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, विकलांग बच्चों की देखभाल और बाधा मुक्त वातावरण।
- विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 - दिव्यांगजनों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन को प्रभावी बनाने और उससे जुड़े मामलों को संबोधित करने के लिए एक अधिनियम है।
- इंचियोन रणनीति - इस रणनीति का उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों के एशियाई और प्रशांत दशक के पूर्ण और प्रभावी कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के लिए सदस्य और सहयोगी सदस्य देशों को तकनीकी परामर्श और सहायता प्रदान करना है।

वैचारिक पृष्ठभूमि

शैक्षिक नेता समावेशन की अवधारणा को नीति से व्यवहार में बदलने के प्रयास में महत्वपूर्ण है। नेतृत्व संस्कृति, नीतियों और प्रथाओं को लागू करने और स्थापित करने हेतु आवश्यक है जिसमें कक्षा शिक्षण और संबंध, बोर्ड बैठक, शिक्षक पर्यवेक्षण, परामर्श सेवाएं, चिकित्सा, देखभाल,स्कूल यात्राएं, बजटीय आवंटन और जहां तक संभव हो सके विद्यार्थियों के माता-पिता और समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ समायोजन स्थापित करना आदि। (हंट एट ऑल.,2024)। समावेशी नेतृत्व प्राप्त करना समावेशी विद्यालय संस्कृत नीति के साथ-साथ मानसिकता और सहयोग पर भी आधारित है। विद्यालय के नेताओं की समावेशी मूल्य को अपनाने की तत्परता, शिक्षकों की सहभागिता, सक्रीय भूमिका और सुदृढ़ सहायता संरचना की उपलब्धता यह सभी महत्वपूर्ण तत्व हैं।(अल्बुलेस्कु एट ऑल.,2025)। समावेशी विद्यालय नेतृत्व समावेशी शिक्षा में शोध पद्धतियों के लिए एक समग्र विद्यालय परिवर्तन हेतु योगदान दे सकते हैं। यह शिक्षकों के शैक्षणिक आशावाद को प्रभावित करते हैं और विद्यालयों में शिक्षकों के सहयोग और समावेशी ज्ञान को अंतरराष्ट्रीय आधार पर योगदान प्रदान कर सकते हैं।(एडम्स एट ऑल., 2025)। व्यक्तिगत शिक्षा योजना के कार्यान्वयन की दिशा में परिवर्तनकारी नेतृत्व का प्रभाव सहयोगात्मक संरचनाओं द्वारा पूरी तरह से मध्यस्थ होता है जबकि निर्देशात्मक नेतृत्व का प्रभाव बना रहता है। नेतृत्व शैली इस बात से जुड़ी होती है कि विद्यालय नेता सहयोग को बढ़ावा देने के लिए अपने कार्यक्षेत्र में किस प्रकार का बदलाव करते हैं। (लैंब्रेच्ट एट ऑल.,2020)

समावेशी शिक्षा में शैक्षिक नेताओं की भूमिका और प्रभाव पर बहुत कम साहित्य उपलब्ध है। न ही ऐसा कोई साहित्य है जो यह बताता हो कि नेतृत्व के पुराने मॉडल और आदतें समावेशी शिक्षा को वास्तविकता बनने से कैसे रोकती हैं। सभी प्रकार के अध्ययनों की आवश्यकता है, विशेष रूप से मात्रात्मक अध्ययनों की जो समावेशी शिक्षा के लिए विद्यालय नेताओं के विश्वासों, दृष्टिकोणों और प्रभावशीलता का विश्लेषण करें।

अध्ययन का आवश्यकता

समावेशी शिक्षा नीतियों को लागू करने शिक्षा में उत्पन्न बाधाओं की पहचान करने, समावेशी स्कूल संस्कृतियों को बढ़ावा देने, सकारात्मक परिणाम की प्राप्ति, विद्यार्थियों की समस्याओं को को समझने, व्यवस्थाओं का अवलोकन करने संसाधनों की कमी का पता लगाने आदि कार्यों को ध्यान में रखते हुए अध्ययन की आवश्यकता है।

शोध प्रश्न

- समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं क्या है?
- समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका क्या है?

परिणाम

उद्देश्य नंबर -1- समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषताएं क्या है।

समावेशी नेतृत्व की प्रमुख विशेषता समानता और न्याय में विश्वास है, जहाँ प्रत्येक बच्चे को बिना किसी भेदभाव के समान समझा जाता है। ऐसा नेतृत्व सभी हितधारकों जैसे शिक्षकों, अभिभावकों और समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल करके सहयोगात्मक संस्कृति का निर्माण करता है। इसमें लचीलापन और नवाचार होता है ताकि पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों को दिव्यांग बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार ढाला जा सके। समावेशी नेतृत्व की यह भी जिम्मेदारी है कि वह रैंप, ब्रेल लिपि, सहायक उपकरण जैसी आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करे और शिक्षकों के सतत व्यावसायिक विकास हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था को ध्यान में रखें।

उद्देश्य नंबर -2- समावेशी शिक्षा के प्रभावी क्रियान्वयन में शैक्षिक नेतृत्व की भूमिका क्या है।

समावेशी शिक्षा में नेतृत्व की भूमिका केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। एक प्रभावी समावेशी नेता विद्यालय में ऐसी संस्कृति का निर्माण करता है जहाँ विविधता को बोझ नहीं, बल्कि शक्ति के रूप में देखा जाता है। वर्तमान भारतीय संदर्भ में यह और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिव्यांग बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रखा जाता है।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध गुणात्मक एवं सैद्धांतिक प्रकृति का है इसमें दस्तावेज विश्लेषण विधि उपयोग कर द्वितीय स्रोतों दद्वितीयक स्रोत द्वारा जानकारी एकत्र कर समावेशी नेतृत्व की विशेषताओं और भूमिका का सैद्धांतिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।

निष्कर्ष

समावेशी नेतृत्व केवल प्रशासनिक प्रबंधन नहीं, अपितु एक मूल्य-आधारित परिवर्तनकारी प्रक्रिया है। इसकी प्रमुख विशेषताएँ - समता एवं सामाजिक न्याय में अटूट विश्वास, लोकतांत्रिक निर्णय-प्रक्रिया, सहयोगात्मक संस्कृति का विकास, पाठ्यचर्या में लचीलापन, बाधा-मुक्त अधिगम वातावरण एवं संसाधनों का न्यायसंगत प्रबंधन, शिक्षकों का सतत व्यावसायिक सशक्तिकरण तथा दिव्यांग बच्चों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण एवं सम्मानजनक दृष्टिकोण ही समावेशी शिक्षा को सार्थक बनाते हैं।

सुझाव

- वर्तमान में समावेशी शिक्षा हेतु चल रहे कार्यक्रमों की उपयोगिता का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा हेतु दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की पहुंच सामान्य स्कूलों में किस स्तर की है, का अध्ययन करना किया जाना चाहिए।
- विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की समस्याओं को समझने उनका समाधान करने के लिए राज्य और जिले स्तर पर जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन का अध्ययन किया जाना चाहिए।
- समावेशी शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व की दृष्टिकोण को अपनाने वाले विद्यालयों का अध्ययन किया जाना चाहिए।

संदर्भ सूची

एडम्स, डी., मोहम्मद, ए., मूसा, वी., शरीफ़ा, एम., एवं टैन, के. एल. (2025)। Toward effective inclusive practices: Dynamics among school leadership, academic optimism, and teacher collaboration. *International Journal of Developmental Disabilities, 71*(6), 867–878. https://doi.org/10.1080/20473869.2025.2479746

अल्बुलेस्कु, आई., मानेआ, ए.-डी., अल्बुलेस्कु, एम., स्टैन, सी., एवं एंड्रोनाचे, डी. (2025)। Perceptions of inclusive leadership and its implications for achieving socio-educational performance. *Social Welfare: Interdisciplinary Approach, 15*, 213–237. https://doi.org/10.15388/SW.2025.15.12

European Agency for Special Needs and Inclusive Education. (2020)। *Inclusive school leadership: A practical guide to developing and reviewing policy frameworks*. European Agency for Special Needs and Inclusive Education. https://www.european-agency.org

हंट, पी., म्प्राह, डब्ल्यू., पोर्टर, जी., रिचलर, डी., साइडर, एस., स्पेक्ट, जे., एवं स्वेंसन, एस. (2024)। *Lead to include: Educational leadership for inclusive education* (ED/GEMR/MRT/2024/BP1/04)। UNESCO Global Education Monitoring Report Team. https://doi.org/10.54676/TYEN6998

लैम्ब्रेक्ट, जे., लेनकाइट, जे., हार्टमैन, ए., एहलर्ट, ए., निग्गे, एम., एवं स्पोरर, एन. (2022)। The effect of school leadership on implementing inclusive education: How transformational and instructional leadership practices affect individualised education planning. *International Journal of Inclusive Education, 26*(9), 943–957. https://doi.org/10.1080/13603116.2020.1752825

मानव संसाधन विकास मंत्रालय। (2020)। *राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (National Education Policy 2020)*। भारत सरकार। https://education.gov.in

यूनेस्को। (2019)। *N for nose: State of the education report for India 2019: Children with disabilities*। UNESCO New Delhi Cluster Office. https://www.unesco.org